कोटा (राजस्थान) में होने वाले 'व्यापार एवं उद्योग समृद्धि संवाद' में माननीय अध्यक्ष का भाषण

.....

श्री पीयूष गोयल, वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री;

कोटा व्यापार महासंघ और लघु उद्योग संघ, कोटा के सभी पदाधिकारीगण और सदस्यगण;

उद्यमीगण, देवियो और सज्जनो;

.....

आज आप सभी के बीच यहाँ आकर और 'व्यापार एवं उद्योग समृद्धि संवाद' में भाग लेकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। वर्तमान समय में हम सब एक नए भारत के सपने को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं।

अमृत काल में हमें यह अवसर मिला है और हमें भारत को प्रगति और निरंतर समृद्धि के पथ पर अग्रसर कर मां भारती की उम्मीदों पर खरा उतरना है।

भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि देश के हर कोने में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा दिया जाए ताकि देश में समावेशी विकास हो सके। हम इस विकसित, प्रगतिशील, परिवर्तनशील और शक्तिशाली भारत की विकास यात्रा में प्रत्येक नागरिक का साथ चाहते हैं तथा उन्हें इसका लाभ पहुंचाना चाहते हैं।

मुझे यह जानकर बहुत खुशी हो रही है कि कोटा व्यापार महासंघ और कोटा लघु उद्योग संघ कोटा जिले की औद्योगिक क्षमता का पूर्ण तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपके प्रयासों की सराहना करता हूं और आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग पड़ोसी जिलों के व्यापारियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं।

वोकल फॉर लोकल पहल को पूरे देश में जबर्दस्त समर्थन मिला है। भारत में घरेलू विनिर्माण उद्योग का इस्तेमाल करके, वोकल फॉर लोकल पहल के माध्यम से हम देश को विनिर्माण और आपूर्ति के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकते हैं। देश भर के, विशेषकर हमारे राजस्थान के कारीगर शानदार उत्पाद बनाते हैं।

हालाँकि, उन्हें प्रोत्साहित करने, बढ़ावा देने और एक सुरक्षित आजीविका और निश्चित संवृद्धि दिये जाने की आवश्यकता है जिसके वे वास्तव में हकदार भी हैं। नीति निर्माताओं, प्रशासकों, उद्यमियों और उपभोक्ताओं के रूप में यह हम में से प्रत्येक का कर्तव्य है कि हम उनके भले के लिए आवश्यक कदम उठाएँ।

विकास कभी भी पृथक्करण में नहीं होता है। जब स्थानीय व्यापार और उद्योग एक साथ विकसित होंगे तो ही क्षेत्र का संपूर्ण सामाजिक-आर्थिक विकास होगा। हमें बस सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के संकल्प के साथ काम करना है।

भारत सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया पहल, इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर डेव्लपमेंट प्रोग्राम, इज ऑफ डूइंग बिज़नस, राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली, एम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान (एनएमपी), राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, प्रॉडक्शन लिंकड इंसेंटिव स्कीम, इंडियन फुटवेयर एंड लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम (आईएफएलडीपी), जैसी कई योजनाएं और पहल शुरू की हैं।

हाल ही में पारित जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 से इज ऑफ लिविंग और इज़ ऑफ डूइंग बिज़नस को और बढ़ावा मिला है। इस अधिनियम में 19 मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित 42 केंद्रीय अधिनियमों के 183 उपबंधों को अपराधों की श्रेणी से हटाने के लिए संशोधन किया गया है।

मुझे यह कहते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि भारत के व्यापार और उद्योग क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय परिवर्तन आए हैं, जिनके परिणामस्वरूप देश एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने भारत के व्यापारिक और

औद्योगिक परिदृश्य में योगदान देने वाले सभी प्रमुख कारकों पर काम किया है और इनमें सुधार भी किया है।

भारत ने लगातार मजबूत आर्थिक विकास दर का प्रदर्शन किया है, जिससे यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। सूचना प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, सेवाओं और कृषि सहित विभिन्न प्रकार के उद्योगों द्वारा संचालित, देश की जीडीपी में महत्वपूर्ण विस्तार देखा गया है।

हमने एक जीवंत स्टार्ट-अप इकोसिस्टम देखा है। बढ़ते स्टार्ट-अप इकोसिस्टम के साथ भारत नवाचार और उद्यमिता के केंद्र के रूप में उभरा है।

हमारे पास युवा और गतिशील कार्यबल है, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों व्यवसायों के लिए एक मूल्यवान संपत्ति बन गया है। शिक्षा और कौशल विकास पर जोर देने के साथ, हम एक कुशल कार्यबल विकसित करने में सफल रहे हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में उच्च योग्य पेशेवर हैं।

भारत की खुला बाजार नीतियों और इज़ ऑफ डूइंग बिज़नस पहलों के कारण एफडीआई में अत्यधिक वृद्धि हुई है। आज, बहुराष्ट्रीय निगम भारत को एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में देखते हैं, जो विभिन्न उद्योगों के विकास में योगदान देता है।

हम अपने निर्माण क्षेत्र में तेज़ी लाने में सफल हुए हैं। “मेक इन इंडिया” पहल के अंतर्गत इस बात को समझा गया है कि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए “ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस” सबसे ज्यादा ज़रूरी तत्व है। “ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस” के मामले में विश्व बैंक द्वारा जारी रैंकिंग में भारत बड़ी छलांग लगाते हुए 130वें रैंक पर पहुँच गया है।

औद्योगिक लाइसेंस (आईएल) और औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आईईएम) के लिए आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है और अब यह सेवा उद्यमियों के लिए चौबीसों घंटे (24X7) उपलब्ध है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सेवा के माध्यम से विभिन्न सरकारों और सरकारी एजेंसियों से एक ही स्थान पर अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किए जा सकते हैं। सरकार ने एक आधुनिक दिवाला संहिता भी तैयार की है जिससे कारोबार को बंद करना आसान हो जाएगा।

‘मेक इन इंडिया’ पहल ने विनिर्माण क्षेत्र में घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया है और ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में उद्योगों के विकास को भी गति प्रदान की है।

हम सभी जानते हैं कि भारत की निर्माण क्षमता और निर्यात में लगातार वृद्धि हो रही है जिससे वैश्विक आपूर्ति शृंखला में भारत की स्थिति मजबूत होती जा रही है। भारत में घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलें की गई हैं । इनमें माल और सेवा कर लागू करना, कॉर्पोरेट कर में कटौती, वित्तीय बाज़ार सम्बन्धी सुधार, सरकारी बैंकों का समामेलन, चार श्रम संहिताओं का अधिनियमन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में सुधार, कार्य हेतु पूरी की जाने वाली शर्तों में कमी, सरकारी ख़रीद प्रक्रिया के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत उपाय, चरणबद्ध निर्माण कार्यक्रम आदि शामिल हैं।

डिजिटल प्रौद्योगिकियां अपनाए जाने और स्मार्टफ़ोन के उपयोग से भारत में कारोबार करने का तरीका पूरी तरह बदल गया है। डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम, ई-कॉमर्स, और डिजिटल सेवाओं में भारी वृद्धि हुई है, जिससे कारोबारों के लिए अनेक नए अवसर उत्पन्न हुए हैं।

इस वर्ष जनवरी में लगभग 200 बिलियन डालर (लगभग 2 लाख करोड़ रूपए) के तकरीबन आठ बिलियन (800 करोड़) लेनदेन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से किए गए थे। आज भारत में किए जा रहे कुल भुगतानों में से 40 प्रतिशत भुगतान डिजिटल माध्यम से किए जा रहे हैं।

यह खुशी की बात है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था पहले पूरी तरह नकद आधारित थी, आज वहीं छोटे से छोटा भुगतान भी डिजिटल माध्यम से किया जा रहा है।

जैसाकि मुझे बताया गया है, इनमें से लगभग 50 प्रतिशत भुगतान छोटे या माइक्रो भुगतान होते हैं, जैसेकि किसी लेखन सामग्री के लिए दस रूपए या फल खरीदने के लिए 200 रूपए का किया गया भुगतान।

हम सभी जानते हैं कि भारत परिवहन, लॉजिस्टिक्स, और नवीकरणीय ऊर्जा सहित अवसंरचना विकास में भारी मात्रा में निवेश कर रहा है। कनेक्टिविटी में सुधार और संधारणीय अवसंरचना के फलस्वरूप भी कारोबार करने में आसानी बढ़ रही है और लागत में कमी आ रही है।

इसके अलावा, मैं यहाँ उपस्थित उद्यमियों को बताना चाहता हूँ कि आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के दृष्टिकोण को बहुत महत्व दिया जाता है और भारत बहुत दृढ़ता के साथ अपना पक्ष रखता है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों और दूसरे देशों के साथ साझेदारी के कारण भारत का कारोबार अनेक बाज़ारों में फैल गया है। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार समझौतों ने भारतीय उद्यमों की वैश्विक बाज़ार तक पहुँच बनाकर नए अवसर उत्पन्न किए हैं।

जी20 न्यू डेल्ही लीडर्स डिक्लेरेशन में मजबूत, सतत, संतुलित और समावेशी विकास पर बल दिया गया है। विकास को गति देने और संधारणीय तरीके से आर्थिक परिवर्तन लाने में निजी उद्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए इस डिक्लेरेशन में निजी क्षेत्र के साथ मिलकर काम करने का संकल्प लिया गया है।

इन सब बातों के साथ-साथ, स्टार्ट अप्स और एमएसएमई को विकास का “नेचुरल इंजन” माना जाता है जो ‘नवोन्मेष और रोजगार सृजन’ के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन ला सकते है। उन्हें और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए भारत की जी 20 अध्यक्षता के दौरान, स्टार्ट अप 20 एंगेजमेंट ग्रुप स्थापित किया गया है ।

एमएसएमई भारत में प्रमुख नियोक्ता हैं जो विशेषकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में श्रमबल को रोजगार देते हैं। बेरोजगारी दूर करने में इनका बड़ा योगदान है। विनिर्माण, सेवा और कृषि क्षेत्रों सहित एमएसएमई अनेक क्षेत्रों में विद्यमान हैं।

ये वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और अन्य कार्यकलापों से भी जुड़े हुए हैं। हमारे एमएसएमई क्षेत्र में नवोन्मेष और उद्यमशीलता की कोई कमी नहीं है। अनेक स्टार्ट

अप्स और नवोन्मेषी उद्यम एमएसएमई की श्रेणी में आते हैं और नवोन्मेष के केंद्र के रूप में भारत की साख बढ़ा रहे हैं।

इनका भारत के निर्यात क्षेत्र में बड़ा योगदान है। इनके माध्यम से काफी मात्रा में निर्यात होता है, जिससे देश विदेशी मुद्रा अर्जित करता है और विश्व व्यापार में देश का हिस्सा भी बढ़ता है।

'उद्यमी भारत' कार्यक्रम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सशक्त बनाने की दिशा में सरकार द्वारा पहले दिन से ही किए जा रहे प्रयासों और सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को समय पर आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए मुद्रा योजना, इमर्जेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना और पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए कोष की योजना (स्फूर्ति) आदि जैसी अनेक पहलें शुरू की हैं।

एमएसएमई के प्रदर्शन में सुधार और विकास में तेजी लाने के लिए रैंप योजना शुरू की गई है जिसका उद्देश्य मौजूदा एमएसएमई योजनाओं से होने वाले लाभ को बढ़ाने के साथ राज्यों में एमएसएमई योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना और उनकी कवरेज बढ़ाना है।

मुझे यह जानकर बहुत खुशी हो रही है कि कोटा जिले के 20 औद्योगिक क्षेत्रों ने राज्य के साथ-साथ देश के औद्योगिक जगत में भी अपना एक मुक़ाम बना लिया है। कोटा जिले से हर साल कई औद्योगिक उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है।

इन उत्पादों में रेयॉन टायर यार्न कॉर्ड, रेयान थायर फैब्रिक, कैल्शियम कार्बाइड, कॉपर और कॉपर अलॉय, एंटीमनी, सल्फेट, कैल्शियम फ्लोराइड, लेड स्टीयरेट, लेड अलॉय, ऑक्साइड और मेटालिक, नेचुरल स्टोन, सोया मील, सोया ऑयल केक, टेक्सटाइल मशीनरी पार्ट्स तथा सैंड और लाइम स्टोन का निर्यात शामिल है।

एक जिला एक उत्पाद पहल के तहत राज्य सरकार द्वारा कोटा पत्थर को औद्योगिक उत्पाद और धनिया को कृषि उत्पाद के रूप में बढ़ावा दिया गया है।

तथापि, कोटा की क्षमता यहीं तक सीमित नहीं है। इस जिले में देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरने की संभावनाएँ हैं। सेवा क्षेत्र में, कोचिंग संस्थान आकर्षण का प्रमुख केंद्र हैं। इसके अलावा, कोटा में पैकेज्ड फूड उद्योग, प्रिंटिंग प्रेस, हॉस्टल्स, बेकरी यूनिट्स, स्कूल फर्नीचर तथा स्टील फर्नीचर जैसे क्षेत्रों में एक विश्व स्तरीय हब के रूप में उभरने की क्षमता है।

जहां तक कुटीर और ग्रामोद्योग का संबंध है, विशेष रूप से चमड़े से बनी चीजों, दोना-पत्तल, लकड़ी के खिलौने, हैंडलूम चादर, सरकंडा और खस उद्योग, ब्रूम उद्योग,वुडवर्क आदि के लिए अभी और अधिक इकाइयों की स्थापना की जा सकती है।

हर साल कोटा डोरिया साड़ियों का विश्व भर के विभिन्न देशों में निर्यात किया जाता है, जो यह दर्शाता है कि पूरे विश्व में गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की अधिक मांग होती है।

यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस विश्वस्तरीय औद्योगिक अवसंरचना स्थापित करने और वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और स्थानीय निवेश को बढ़ावा देने के लिए, वस्त्र मंत्रालय ने 7 मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (पीएम मित्र) पार्क स्थापित करने हेतु एक अधिसूचना जारी की है।

ये परिधान पार्क एक ही स्थान पर कताई, बुनाई, प्रसंस्करण/रंगाई, प्रिंटिंग और परिधान तैयार करने के लिए इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल वैल्यू चेन बनाने का अवसर प्रदान करेंगे । हम आशा करते हैं कि राजस्थान राज्य इस तरह के हब से लाभान्वित होगा ।

भारत का समृद्ध व्यापार और उद्योग परिदृश्य इसकी रेज़िलियंस, अनुकूलनशील और आर्थिक विकास के प्रति इसकी प्रतिबद्धता का जीवंत प्रमाण है। स्टार्ट-अप्स की बढ़ती संख्या, कुशल कार्यबल की उपलब्धता और निवेश हेतु अनुकूल परिवेश के साथ, भारत एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में सफलता के पथ पर अग्रसर है। वैश्विक व्यापार जगत में भारत का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है और भावी वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देने में भी भारत की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ कोटा व्यापार महासंघ और कोटा के लघु उद्योग संघ के भावी प्रयासों में सफलता के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।